भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2433

सोमवार, 18 दिसम्बर, **202**3/27 अग्रहायण, **194**5 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए स्वीकृत निधि

†2433. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नोट किया है कि हाल ही में, 2022 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व के सर्वोत्तम गांवों की सूची में भारत के एक भी गांव का नाम नहीं है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए स्वीकृत और प्रयुक्त राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा योजनाओं की प्रभावकारिता के संबंध में कोई आकलन किया है और कोई मानदंड तय किया है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क स्थापित करने के साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन करने और भारत प्राचीन धरोहर के प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) क्या सरकार की बाधारहित समन्वयन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी हां, महोदय। वर्ष 2022 में यूएनडब्ल्यूटीओ के उन्नयन कार्यक्रम हेतु नागालैंड में खोनोमा गाँव का चयन किया गया था।

वर्ष 2021 में तेलंगाना में पोचम्मपल्ली गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया था। 2023 में गुजरात में धोरडो गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में और मंडला, मध्य प्रदेश को वर्ष 2023 के लिए उन्नयन कार्यक्रम हेतु चुना गया है।

(ख) से (घ): ग्रामीण पर्यटन के विकास और संवर्धन से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का सृजन किया जा सकता है और आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए स्थानीय समुदायों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के बीच

समन्वय और ताल-मेल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप- आत्मनिर्भर भारत की ओर एक पहल नामक दस्तावेज़ तैयार किया है।

पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्रामीण परिपथ को पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए थीमेटिक परिपथ में से एक के रूप में चिह्नित किया गया था। ग्रामीण पर्यटन परिपथ के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केन्दित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) 16 फरवरी, 2023 को ग्रामीण पर्यटन गाँव पोर्टल शुरू किया गया था। इस वेबसाइट पर भारत में ग्रामीण पर्यटन गंतव्यों, भारत में ग्रामीण होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन आदि हेतु सरकारी और औद्योगिक पहलों के बारे में जानकारी दी गई है।

(ii) पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन हेतु केन्द्रीय नोडल एजेंसी (आईआईटीटीएम) के सहयोग से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता का आयोजन किया। अंतिम मूल्यांकन में भारत के 35 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों को चुना गया।

(iii) पर्यटन मंत्रालय 01.01.2020 से अखिल भारत अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ)/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल चला रहा है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों सहित देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों के एक समूह का सृजन करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म तैयार करना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए मूलभूत (आईआईटीएफ), उच्च (आईआईटीजी- विरासत और एडवेंचर), मौखिक विदेशी भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है। उम्मीदवार किसी भी स्थान से और किसी भी समय तथा अपनी सुविधानुसार इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं।

(iv) प्रभावी और उपयुक्त कनेक्टिविटी किसी पर्यटक गंतव्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसी उद्देश्य से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आरसीएस- उड़ान योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को किफायती बनाते हुए इसे सुगम बनाना/प्रोत्साहित करना है। प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से चैम्पियन

सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। वर्तमान में 53 पर्यटन मार्ग प्रचालनरत हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-**I)** मुख्य नेटवर्क में असंबद्ध पात्र रिहायशी स्थानों तक एक ऑल-वेदर रोड द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक बार किया गया विशेष हस्तक्षेप है।

इसके पश्चात ग्रामीण सड़कों के उन्नयन, एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाले मार्गों तथा मुख्य ग्रामीण लिंक्स के जरिए 1,25,000 कि.मी. के समेकन के लिए नए हस्तक्षेप/वर्टिकल्स यथा पीएमजीएसवाई-**II,** वामपंथी उग्रवाद बहुल क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई-**III** को पीएमजीएसवाई के दायरे में शामिल किया गया।

प्रारम्भ से लेकर दिनांक 13.12.2023 तक 8,14,522 कि.मी. में से 1,86,**541** लम्बी सड़कों और 11,587 पुलों को 3,76,472.36 करोड़ रु. की परियोजना मूल्य की स्वीकृति दी गई है जिनमें से 3,12,986.17 करोड़ रु. (राज्य के हिस्से सहित) के निवेश से 7,49,363 कि.मी. में से **1,77,628** लम्बी सड़कों और 8,**435** पुलों का काम पूरा कर लिया गया है।

पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के विशाल नेटवर्क ने ग्रामीण पर्यटन की क्षमता रखने वाले अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है। इस प्रकार पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन में सहायता की है।

(ड.): जी नहीं, महोदय। निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में ग्रामीण पर्यटन के विकास संबंधी एक कार्य बल का गठन किया गया है जिसमें चिह्नित केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और औद्योगिक हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

****

अनुबंध

श्री रितेश पाण्डेय द्वारा ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए स्वीकृत निधि के संबंध में दिनांक 18.**12**.202**3** को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2433 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में विवरण

देश में स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि*	भौतिक स्थिति **(%)**	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	बिहार	**2017-18**	भितिहरवा - चंद्राहिया – तुर्कौलिया का विकास	**44.27**	**39.96**	**39.96**	पूर्ण	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम
2.	केरल	ग्रामीण परिपथ **2018-19**	मलानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	**57.35**	**30.98**	**25.14**	**54.60**	केरल पर्यटन विकास निगम

* इसमें नई वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार सीएनए को जारी की गई राशि शामिल है।

****